



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

17 वैशाख 1940 (श10)  
(सं0 पटना 421) पटना, सोमवार, 7 मई 2018

सं0 04 / नि.अधि.कैश क्रेडिट-08 / 17 (खण्ड-A)-948  
सहकारिता विभाग

संकल्प

19 मार्च 2018

**विषय :-** राज्य में अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को राज्य खाद्य निगम से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता के कारण प्रबंधकीय अनुदान मद में 259625000/-(पचीस करोड़ छियानवे लाख पचीस हजार) रुपये की स्वीकृति के संबंध में।

राज्य में किसानों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को सुदृढ़ एवं सशक्त करने के लिए उनके कृषि उत्पाद का लाभकारी मूल्य प्रदान करने एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न सहकारी संस्थाओं पैक्स/व्यापारमंडल/जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक/राज्य सहकारी बैंक को राज्य खाद्य निगम से भुगतान प्राप्ति में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता के कारण प्रबंधकीय अनुदान का निर्णय लिया गया है।

सहकारी संस्थाओं/बैंकों को राज्य खाद्य निगम से प्राप्त भुगतान में विलम्ब एवं अतिरिक्त ब्याज देयता की कठिनाईयों के मद्देनजर प्रत्येक वर्ष आपूर्ति की गई चावल की मात्रा के अनुरूप रु. 10 प्रति क्विंटल की दर से पैक्स एवं व्यापारमंडलों को तथा रु. 5 प्रति क्विंटल की दर से जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों को तथा 50 पैसे प्रति क्विंटल की दर राज्य सहकारी बैंकों प्रबंधकीय अनुदान की राशि राज्य योजना मद से उपलब्ध करायी जानी है। वर्ष 2017-18 के लिए औसत अधिप्राप्ति धान की मात्रा कुल 25 लाख मे.टन के अनुपातिक चावल 16.75 लाख मे.टन (@67%) के लिए उक्त निर्णय के आलोक में गणना तालिका निम्न है :-

1. कुल धान अधिप्राप्ति की मात्रा (अनुमानित)-25 लाख मे.टन
2. अधिप्राप्ति धान के समतुल्य सी.एम.आर. की मात्रा-16.75 लाख मे.टन
3. प्रबंधकीय अनुदान की राशि सी.एम.आर. पर 259625000 रु. (16750000 क्विंटल @ 15.50)

प्रबंधकीय अनुदान मद में स्वीकृत रु. 259625000/-(पचीस करोड़ छियानवे लाख पचीस हजार) के विरुद्ध वित्तीय वर्ष 2017-18 में रु. 5,00,00,000/-(पाँच करोड़) का उपबंध प्राप्त है। राज्य सरकार द्वारा प्रबंधकीय अनुदान मद में रु. 259625000/- (पचीस करोड़ छियानवे लाख पचीस हजार) व्यय करना स्वीकृत किया गया है।

2. प्रबंधकीय अनुदान मद की स्वीकृत राशि बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना को एकमुश्त स्थानान्तरित की जायेगी। बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना सहकारिता विभाग के पोर्टल पर मोबाईल ऐप पर संधारित ऑकड़ों के आधार पर समितिवार CMR की आपूर्ति (राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की गई मात्रा एवं उक्त मात्रा के विरुद्ध राज्य खाद्य निगम से प्राप्त भुगतान की प्रविष्टि) के अनुरूप निर्धारित दर (पैक्स/व्यापार मंडलों को 10/- रु. प्रति क्विंटल, जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक को 5/- रु. प्रति क्विंटल एवं राज्य सहकारी बैंक को 0.50/- रु. प्रति क्विंटल) से प्रबंधकीय अनुदान की राशि समितियों के खाते में एक मुश्त स्थानान्तरित करेगा।

3. बिहार राज्य सहकारी बैंक के द्वारा उक्त राशि का विचलन अन्य मदों में नहीं किया जायेगा।

बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना द्वारा स्वयं के लिए भी तदनु रूप निर्धारित दर से राशि की निकासी कर ली जायेगी।

4. प्रत्येक जिले के लिए कुल वितरित राशि का जिलावार/बैंकवार विस्तृत प्रतिवेदन बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना द्वारा नियमित रूप से मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

सावधिक रूप से व्यवहृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., पटना द्वारा मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

अंकेक्षण हेतु सभी अभिलेख सभी संबंधित स्तरों पर संधारित रहेगा।

5. प्रबंधकीय अनुदान मद की राशि के समुचित वितरण एवं क्रियान्वयन की समीक्षा की जवाबदेही संबंधित प्रमंडलीय संयुक्त निबंधक की होगी, जो नियमित रूप से इसकी समीक्षा कर यथावांछित निदेश संसूचित करेंगे।

6. इस योजना के संबंध में विभागीय स्वीकृति पत्र एवं विभागीय दिशा-निर्देश लागू होगा। यह संकल्प तत्काल प्रभाव से राज्य में प्रभावी समझा जायेगा।

**आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।**

बिहार के राज्यपाल के आदेश से,  
सुरेश चौधरी,  
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 421-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>